



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]
No. 38]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 14, 1999/बैशाख 24, 1921
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 14, 1999/VAISAKHA 24, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 1999

सं. टी ए एम पी/1/98-सी एच पी टी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार चेन्नई पत्तन न्यास को देय समपहरण-पूर्व और समपहरण-पश्चात् वसूल किए जाने वाले प्रभाश्रों के संबंध में चेन्नई पत्तन न्यास (सी.एच.पी.टी.) के मानों का संशोधन करता है।

मामला सं. टी ए एम पी/1/98-सी एच पी टी

चेन्नई पत्तन न्यास

..... आवेदक

आदेश

(13 अप्रैल, 1999 को पारित)

यह मामला समपहरण-पूर्व एवं समपहरण-पश्चात् के प्रभाश्रों से संबंधित चेन्नई पत्तन न्यास (सी एच पी टी) के दरमानों के संशोधन के लिए उनसे सितम्बर, 98 में प्राप्त एक प्रस्ताव से संबंधित है।

2. प्रस्ताव के संबंध में सामान्य संवीक्षा कार्यवाही की गई। टिप्पणियों के लिए प्रतियां सीमाशुल्क समाहर्ता (चेन्नई) और मद्रास चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एम सी सी आई) को भेजी गई थी। किसी भी पक्षकार से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले पर जनवरी, 99 में पसन स्तर पर संयुक्त सुनवाई की गई। सी एच पी टी के अतिरिक्त संयुक्त सुनवाई में सीमा शुल्क समाहर्ता, और एम सी सी आई, सदर्न इंडिया चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एस आई सी सी आई) को भी आमंत्रित किया गया। तथापि, संयुक्त सुनवाई में सी एच पी टी और एम सी सी आई ही उपस्थित हुए। सीमाशुल्क समाहर्ता और एस आई सी सी आई नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं हुए।

3.1 इस मामले में संगत तथ्य निम्न प्रकार हैं :—

3.2 सीमाशुल्क प्रविष्टि के बीजकों का मूल्यांकन करते समय अथवा जांच के समय अथवा 'उठाए न गए' माल के रूप में माल को बिक्री के लिए लाए जाने के समय समपहरण आदेश जारी करता है। संदर्भाधीन कार्यों के लिए उपलब्ध सामान्य 'निशुल्क दिवसों' की समाप्ति से समपहरण आदेश की तारीख तक की अवधि को 'समपहरण पूर्व अवधि' माना जाता है।

3.3 सीमाशुल्क को समपहरण आदेश जारी करने के पश्चात् पत्तन न्यास के परिसर से सीमाशुल्क के वेयरहाउस तक माल को ले जाने के लिए समपहरण आदेश की तारीख से 14 दिन (रविवारों और बोर्ड की छुट्टियों सहित) की अवधि की अनुमति है। यह अवधि सामान्य प्रक्रिया में माल के आयात/निर्यात के लिए स्वीकार्य निशुल्क दिनों के अतिरिक्त है। 14 दिन के निशुल्क समय की समाप्ति से सीमाशुल्क वेयर हाउस तक माल को ले जाने की तारीख तक की अवधि को 'समपहरण पश्चात् की अवधि' माना जाता है।

3.4 समपहरण पूर्व अवधि के लिए परोयित/स्टीमर एजेंट/लाइनर एजेंट से सामान्य विलम्ब शुल्क वसूल किया जाता है।

3.5 समपहरण पश्चात् की अवधि के लिए सीमा शुल्क से प्रभार "भण्डारण प्रभारों" के रूप में समपहरण की तारीख से सीमाशुल्क वेयरहाउस तक माल ले जाने की तारीख तक आबद्ध वेयरहाउस में माल के लिए निर्धारित मान के अनुसार किसी दैनिक दर के आधार पर वसूल किए जाते हैं। भण्डारण प्रभारों के अतिरिक्त आधे टन तक के भार के प्रति पैकेज पर 8 रु० की दर से और आधे टन के पैकेज से अधिक भार के पैकेजों के लिए प्रति टन अथवा उसके किसी भाग के लिए 114 रु० की दर पर निष्कासन प्रभार भी वसूल किए जाते हैं।

4. पत्तन स्तर पर संयुक्त सुनवाई में हुई बातों के दौरान निम्नलिखित मुद्दे प्रकट हुए :—

- (i) 'समपहरण पूर्व' और 'समपहरण पश्चात्' की अवधियों के बीच अंतर यथार्थ नहीं है।
- (ii) उदाहरण के तौर पर मुंबई पत्तन न्यास ऐसा अंतर नहीं करता।
- (iii) सीमाशुल्क समपहरण आदेश पारित करने में अत्यधिक लम्बा समय लेता है—कभी-कभी कई महीने और कभी-कभी कई वर्ष (भी)।
- (iv) बहुत-से मामलों में समपहरण आदेश को बाद में निरस्त कर दिया जाता है।
- (v) सीमाशुल्क द्वारा किए गए अनुचित विलम्ब के परिणामस्वरूप पत्तन न्यास के लिए प्रशासनिक, कानूनी और वित्तीय समस्याएं (परिहार्य) उत्पन्न हो जाती हैं।

बहुत-से मामलों में समपहरण आदेशों के निरस्त होने के परिणामस्वरूप ऐसी समस्याएं और बढ़ जाती हैं।

- (vi) अत्यधिक विलम्ब के कारण समपहरण के बहुत से मामलों में पेरिडियों को खोजना अत्यंत कठिन (यदि असंभव नहीं तो) हो जाता है क्योंकि या तो उनका पता गलत होता है अथवा उनका पता नहीं लगता। फलस्वरूप देयताओं को वसूल करने के लिए कानूनी कार्यवाही भी संभव नहीं होती। इसके कारण पत्तन न्यास को पर्याप्त वित्तीय हानि होती है।
- (vii) सीमाशुल्क अधिनियम (1962) के अनुसार समपद्धत माल का स्वामित्व सीमाशुल्क के पास होता है। बिक्री की राशि का विनियोजन भी सीमा शुल्क द्वारा किया जाता है। संबंधित पेरिडि/स्टीमर एजेंट/लाइनर एजेंट का बिक्री से प्राप्त राशि पर कोई दावा नहीं होगा। पत्तन न्यास कार्गो पर लगाए जाने वाले नाममात्र विलम्ब शुल्क प्रभारों के अनुसार समपहरण-पश्चात् प्रभारों के रूप में केवल नाममात्र की राशि वसूल करता है।
- (viii) सभी पहलुओं से पत्तन न्यास सीमा शुल्क द्वारा की गई कार्यवाहियों और विलम्ब के कारण अलाभकारी स्थिति में रहता है। इसलिए 'समपहरण पूर्व' और 'समपहरण पश्चात्' अवधि के बीच अंतर को दूर करने और सीमाशुल्क विभाग से सभी शुल्क वसूल करने के लिए दरमानों को संशोधित करना एक न्यायपूर्ण प्रस्ताव होगा।

5. एम सी सी आई का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रयोक्ताओं ने सी एच पी टी द्वारा किए गए प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की। जैसा पहले बताया गया है कि एस आई सी सी आई नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ और सीमाशुल्क समाहर्ता नोटिस के बावजूद अनुपस्थित रहा।

6. उपर्युक्त तर्कों के आधार पर सी एच पी टी ने दरमानों के संशोधन के अपने प्रस्ताव पर जोर दिया है। तीन संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है जो इस प्रकार हैं:—

- (i) सीमा शुल्क द्वारा समपद्धत माल के लिए निशुल्क दिनों की समाप्ति की तारीख से समपहरण की तारीख तक अथवा निशुल्क दिनों की समाप्ति की तारीख से प्रथम चार महीनों के लिए, इनमें जो भी पहले हो, सीमाशुल्क से 'समपहरण पूर्व' प्रभारों के रूप में उन पर संचित सामान्य शुल्क वसूल किए जाएंगे।

इनकी यह समय-सीमा पहले नहीं थी।

- (ii) समपहरण की तारीख तक समपद्धत माल पर संचित होने वाले न्यास को देय शुल्क समपद्धत माल की बिक्री की राशि से सीमा शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि तक सीमित होंगे। शेष राशि को छोड़ दिया गया माना जाएगा।
- (iii) 8 रु० और 114 रु० की दर पर (जैसा कि उक्त पैरा 3.5 में वर्णित है) सीमा शुल्क से वसूल किए जाने वाले निष्कासन प्रभारों को बढ़ाकर क्रमशः 10 रु० और 115 रु० करने का प्रस्ताव है।
7. इस मामले के संबंध में एकत्र की गई सूचना/ब्यौरे/आंकड़ों के संदर्भ में और सामुहिक विचार-विमर्श के पश्चात् इस प्राधिकरण ने इस मामले को आज अपनी बैठक में अंतिम विचारण के लिए उठाया।
8. जैसा कि उपर्युक्त तथ्यों से मालूम हो जाता है और सी एच पी टी द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर माल के समपहरण से संबंधित समस्याएं पूर्णरूपेण सीमा शुल्क के कारण उत्पन्न होती हैं। सीमा शुल्क द्वारा इस संबंध में किए गए अनुचित विलम्बों से पत्तन न्यास को (परिहार्य) प्रशासनिक, कानूनी और वित्तीय समस्याएं उत्पन्न होने का पता लगा है। सीमाशुल्क का योगदान इस तथ्य से भी साबित किया जा सकता है कि उन्होंने नोटिस के बावजूद इन कार्यवाहियों में भाग लेने का कष्ट नहीं किया।
9. तदनुसार, यह प्राधिकरण समपहरण-पूर्व और समपहरण-पश्चात् के प्रभारों के बारे में सी एच पी टी के दरमानों को संशोधित करने के लिए उनके प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदित करता है:—
- 9.1 अध्याय (IV), मान 'ख'(1)-समपद्धत माल से संबंधित-निःशुल्क दिन के अंतर्गत विद्यमान प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित का प्रतिस्थापन किया जाता है:—
- “सीमा शुल्क द्वारा समपद्धत माल के लिए निःशुल्क दिनों की समाप्ति की तारीख से समपहरण की तारीख तक (अथवा) निःशुल्क दिनों की समाप्ति की तारीख से प्रथम चार महीने के लिए, इनमें जो भी पहले हो सीमा शुल्क से माल पर संचित सामान्य प्रभार माल पर समपहरण-पूर्व प्रभारों के रूप में वसूल किए जाएंगे।
- सीमा शुल्क से समपद्धत माल पर समपहरण की तारीख से सीमा शुल्क के बेयर हाउस तक माल को ले जाने की तारीख तक पुस्तिका-1 के अध्याय X के अंतर्गत आबद्ध बेयर हाउस में माल के लिए मान 'ख' के अनुसार दैनिक दर के आधार पर भंडारण प्रभारों के रूप में समपहरण-पश्चात् के प्रभार वसूल किए जाएंगे। भंडारण प्रभारों के अतिरिक्त आधा टन तक के भार वाले पैकेजों पर 10 रु० और आधा टन से अधिक भार के पैकेजों के लिए प्रतिटन अथवा उसके किसी भाग के लिए 115 रु० की दर पर निष्कासन प्रभार भी वसूल किए जाएंगे।
- समपद्धत माल पर समपहरण की तारीख तक न्यास को देय संचित शुल्क समपद्धत माल की बिक्री की राशि में से सीमाशुल्क से उपलब्ध राशि तक सीमित होगा और शेष शुल्कों को छोड़ दिया गया माना जा सकता है।”
- 9.2 सी एच पी टी के दरमानों की पुस्तिका-1 के अध्याय IV-मान 'ग' प्रभारों में विद्यमान नोट (क)(III) का विलोपन किया जाता है।

एस० मल्लय, अध्यक्ष

[सं० विज्ञापन/III/IV/143/99-असा०]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 1999

No. TAMP/1/98-CHPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby amends the Scale of Rates of Chennai Port Trust (CHPT) in respect of recovery of pre-confiscation and post-confiscation charges due to the Chennai Port Trust (CHPT) as in the Order appended hereto.

Case No.TAMP/1/98-CHPT**The Chennai Port Trust**

...

Applicant**ORDER**

(Passed on this 13th day of April, 1999.)

This case relates to a proposal received in September 98 from the Chennai Port Trust (CHPT) for amendment of its Scale of Rates relating to pre-confiscation and post-confiscation charges.

2. The proposal was subjected to the usual scrutiny process. Copies were sent for comments to the Collector of Customs (Chennai), and the Madras Chamber of Commerce and Industry (MCCI). Comments were received from neither party. In accordance with the procedure prescribed, the case was then taken up for a joint hearing at the port level in January 99. In addition to the CHPT, the Collector of Customs, and the MCCI, the Southern India Chamber of Commerce and Industry (SICCI) was also invited to the joint hearing. At the joint hearing, however, only the CHPT and the MCCI were present. The Collector of Customs and the SICCI were not present in spite of notice.

3.1. The relevant facts of the case are as follows:

3.2. The Customs issue Confiscation Order either at the time of assessing the Bills of Entry or at the time of examination or at the time of goods brought for sale as 'uncleared' goods. The period from expiry of the normal 'free days' available to the cargo in reference to the date of the confiscation order is treated as 'pre-confiscation period'.

3.3. After issue of the confiscation order, the Customs are allowed a period of 14 days (including Sundays and Board holidays) from the date of the confiscation order for removal of the goods from the Port Trust premises to the Customs Warehouse. This period is in addition to the free days admissible to import/export cargo in the normal course. The period from expiry of this 14-day free time to the date of removal of the goods to the Customs Warehouse is treated as 'post-confiscation period'.

3.4. For the pre-confiscation period, normal demurrage is charged from the Consignee / Steamer Agent / Liner Agent.

3.5. For the post-confiscation period, charges are recovered from the Customs as 'Storage Charges' from the date of confiscation up to the date of removal of the goods to the Customs Warehouse on a daily rate basis as per the scale prescribed for goods in the Bonded Warehouse. In addition to the storage charges, removal charges @ Rs.8/- per package weighing up to a half-a-tonne and Rs.114/- per tonne or part thereof for packages weighing more than half-a-tonne are also recovered.

4. During the deliberations in the joint hearing at the port level, the following points emerged:

- (i). The distinction between 'pre-confiscation' and 'post-confiscation' periods is not a realistic one.
- (ii). The Mumbai Port Trust, for example, does not make such a distinction.
- (iii). The Customs take an unduly long time to pass confiscation orders – sometimes several months and, sometimes (even) several years!
- (iv). In many cases, the confiscation order is subsequently cancelled!
- (v). The undue delay caused by the Customs results in (avoidable) administrative, legal, and financial problems for the Port Trust.

The subsequent cancellation of the confiscation orders in many cases further aggravates such problems.

- (vi). In most cases of confiscation, because of undue delay, it becomes very difficult (if not impossible) to locate the consignees as either their addresses are incorrect or they are not traceable. Consequently, even legal action to recover the dues is not possible. This results in substantial financial loss to the Port Trust.
- (vii). Ownership of the goods confiscated vests in the Customs as per the Customs Act (1962). The sale-proceeds are also appropriated by the Customs; the Consignee / Steamer Agent / Liner Agent concerned will have no claim over the sale-proceeds. The Port Trust only recovers the nominal amount as post-confiscation charges as per the nominal demurrage charges leviable on cargoes.
- (viii). In all respects, the Port Trust is placed at a disadvantageous position because of actions taken and delays caused by the Customs. It will be an equitable proposition, therefore, to amend the Scale of Rates to remove the distinction between 'pre-confiscation' and 'post-confiscation' period and collect all dues from the Customs Department.

5. The users who were represented by the MCCI agreed with the proposal made by the CHPT. As earlier stated, the SICCI was not present in spite of notice; and, the Collector of Customs was absent in spite of notice.

6. Based on the arguments cited above, the CHPT have pressed their proposal for a revision of the Scale of Rates. Three modifications have been proposed as follows:

- (i). For goods confiscated by the Customs, the normal dues accrued thereon from the date of expiry of the free days up to the date of confiscation or for the first four months from the date of expiry of free days, whichever is earlier, shall be recovered from the Customs as 'pre-confiscation' charges.

This time limitation was not there earlier.

- (ii). The Trust dues accruing on confiscated goods up to the date of confiscation shall be limited to the extent of amount available from the Customs out of the sale-proceeds of the confiscated goods. The balance being treated as remitted.

This recovery-ceiling and waiver clause was not available earlier.

- (iii). The removal charges recoverable from the Customs at the rate of Rs.8/- and Rs.114/- (as described in para 3.5. above) is proposed to be increased to Rs.10/- and Rs.115/- respectively.

7. With reference to all the information / details / data collected in respect of this case, and based on a collective application of mind, this Authority took up this case for final consideration in its meeting today.

8. As can be seen from the facts given above and the arguments advanced by the CHPT, the problems in respect of confiscation of goods are attributable entirely to the Customs. The undue delays caused in this regard by the Customs have been seen to cause (avoidable) administrative, legal, and financial problems to the Port Trust. The casualness of the Customs can be evidenced also from the fact that they have not bothered to participate in these proceedings in spite of notice.

9. Accordingly, this Authority approves the proposal of the CHPT for amendment to their Scale of Rates regarding recovery of pre-confiscation and post-confiscation charges as given below:-

9.1. The existing provision under Chapter IV, Scale B(1) – relating to confiscated goods – Free days – is substituted by the following:

"For the goods confiscated by Customs, the normal dues accrued on the goods from the date of expiry of the free days upto the date of confiscation (or) for the first four months from the date of expiry

of free days whichever is earlier shall be recovered from the Customs as pre-confiscation charges on the goods.

Post-confiscation charges shall also be recovered on the confiscated goods from the Customs as storage charges from the date of confiscation upto the date of removal of the goods to Customs Warehouse on daily rate basis as per Scale B for goods in the Bonded Warehouse under Chapter X of Book 1. In addition to the storage charges, removal charges @ Rs.10/- per package weighing upto half-a-tonne and Rs.115/- per tonne or part thereof for packages weighing more than half-a-tonne shall also be recovered.

The Trust dues accrued on the confiscated goods upto the date of confiscation shall also be limited to the extent of amount available from the Customs from the proceeds of sale of confiscated goods and the balance dues may be treated as remitted."

9.2. The existing note (a)(iii) in Scale C Charges – Chapter IV of Book 1 of the CHPT Scale of Rates – is deleted.

S. SATHYAM, Chairman

[No. ADVT/III/IV/143/99-Exty]

